Burden due to Port surcharge

753. SHRI JANARDHANA POOJARY: Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the statement of the Chairman, Engineering Export Promotion Council and published in the 'Financial Express' of the 15th June, 1979 captioned "Port Surcharge unnecessary burden"; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF STATE INCHARGE OF THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI CHAND RAM): (a) Yes, Sir.

(b) The Director General of Shipping has been asked to address the Conferences/Rate Agreements, which have imposed congestion surcharge at Calcutta port, to withdraw/reduce the same in view of the eased situation in the Calcutta port.

Super fast trains in Punjab

754. SHRI G. S. TOHRA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state what steps have been taken by Government to run Super fast trains in Punjab?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): Punjab is already served by two pairs of super fast biweekly trains namely 171/172 Bombay Central-Jammu Tawi Express and 173/174 Howrah-Jammu Tawi Himagiri Express. Besides fast deluxe Express trains also connect Punjab with Delhi, Howrah and Bombay. In addition there are about 15 pairs of Mail/Express trains which serve the Punjab area.

बिहार में कृषि और औद्योगिक श्रमिकों के लिये न्यूनतम मजूरी का भुगतान

755. **श्री राम अवधेश सिंह : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार कृषि और औद्योगिक श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजूरी निर्धारित की है ;

(ख) क्या सरकार जानती है कि न तो उद्योगों में और न कृषि में श्रमिकों को न्यूनतम मजूरी दी जा रही है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार कृषि और ठेके पर काम करने वाले श्रमिकों को न्यूनतम मजूरी का भुगतान करने के लिए कुछ ठोस कार्यवाही करने का है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) बिहार सरकार ने कृषि में रोजगार और 30 अन्य अनुसूचित रोजगारों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की है ।

(ख) बिहार सरकार ने सूचित किया है कि इस सम्बन्ध में यह कहना सही नहीं है कि उद्योगों या कृषि में न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा है । तथापि, इस बारे में शिकायतें हैं कि कृषि क्षेत्र के कुछ क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा है ।

(ग) जब कभी राज्य सरकार के ध्यान में न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करने संबंधी मामले लाए जाते हैं, तब अधिनियम के अधीन समुचित कार्यवाई की जाती है । राज्य सरकार ने कार्यान्वियन तंत्र को भी मजबूत बना दिया है, ताकि अधिनियम का प्रवर्तन बेहतर ढंग से हो सके । अभियोजन प्रक्रिया में तेजी लाने के लिये तथा दांडिक उपबन्धों को और कड़ा बनाने के लिये अध्यादेश जारी किया गया है ।

L.D.Cs. serving in Department of Lighthouses and Lightships

756. SHRI V. G. HANDE: Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there are L.D.Cs. at Headquarters Office of the Department of Lighthouses and Lightships having more than 15/20 years of service;

(b) whether it is also a fact that these L.D.Cs. are being offered promotion as U.D.Cs. at Regional Offices and U.D.Cs. from Regional Offices are being transferred to Headquarters Office;

(c) whether Government propose to promote them at Headquarters Office as represented by the Staff Association; and

(d) if so, the facts thereof?

THE MINISTER OF STATE INCHARGE OF THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI CHAND RAM): (a) Yes, Sir.

(b) to (d). Promotion to the grade of U.D.C. in the Department of Lighthouses